मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप, पन्नाधाय व राणा पूंजा की प्रतिमाओं का अनावरण किया

मुख्यमंत्री ने कहा, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से पर्यटक इनकी शूरवीरता की गाथा साथ ले जायेंगे

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि प्रदेश में कोच व खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- उन्होंने भूपाल सागर स्थिल करेड़ा पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की तथा वहाँ उपस्थित संतों से आशीर्वाद लिया।

कपासन, 29 मई(निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की भूमि है। मेवाड़ की धरा स्वाभिमान और शौर्य की एक अमिट मिसाल है। इस भूमि पर आकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप हमारे लिए प्रेरणापुंज हैं, जिन्होंने सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलना सिखाया है। नई पीढ़ी में ऐसे आदर्शों एवं संस्कारों का संचार होना चाहिए।

शर्मा गुरूवार को चित्तौड़गढ़ के भूपालसागर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा की महान विभूतियों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं के अनावरण का यह अवसर आज के दिन को स्वर्णाक्षरों में अंकित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर एवं उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है, ताकि पर्यटक महाराणा प्रताप की शूरवीरता की गाथा अपने साथ लेकर जाएं। साथ ही, हमारी सरकार प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवाड़ की धरा महाराणा प्रताप के साथ ही मां पन्नाधाय एवं राणा पूंजा की धरती है, जिन्होंने दुनिया को कर्तव्यनिष्ठा, शौर्य और अनूठे बलिदान का परिचय दिया। आज का यह दिन भी हमें त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति से हमारी सभ्यता को गौरवशाली बनाने वाले वीरों की याद दिलाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूपाल सागर स्थित करेड़ा पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उपस्थित संतों से आशीर्वाद भी लिया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मां पन्नाधाय और राणा पूंजा की प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम में 108 अवधेशानंद चैतन्य महाराज एवं मुंगाना धाम सांवलिया जी के अनुज दास महाराज, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम दक, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सांसद सीपी जोशी, विधायक अर्जुन लाल जीनगर, अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चिरानिया के नामों को स्वीकार किया गया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में वकील कोटे से नियुक्ति के लिए कुछ अन्य नाम भी विचाराधीन हैं।

मस्क ने ट्रम्प के सलाहकार का पद छोड़ने की घोषणा की

न्यूयॉर्क, 29 मई। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सलाहकार के रूप में अपनी सरकारी भूमिका छोड़ने की घोषणा की है।

मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, एक विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त होने वाला है। मैं राष्ट्रपति ट्रम्प को बेकार खर्च को कम करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

- समझा जाता है कि मस्क ने ट्रम्प के "वन, बिग ब्यूटिफुल एक्ट" का विरोध किया था, जबकि, ट्रम्प इस बिल के बड़े समर्थक हैं, इसी विरोध के चलते मस्क ने ट्रम्प के सलाहकार का पद छोड़ने की घोषणा की है।

मस्क ने सीबीएस न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में मंगलवार को 'वन, बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट' की आलोचना की थी। उन्होंने कर कटौती और बढ़े हुए आव्रजन प्रवर्तन के मिश्रण वाले इस कानून को 'बहुत बड़े खर्च वाला विधेयक' बताया था और कहा था कि यह संघीय घाटे को बढ़ाता है और सरकारी दक्षता विभाग के काम को कमज़ोर करता है। वहीं, ट्रम्प ने बुधवार को अपने विधेयक का बचाव करते हुए कहा, मैं इसके कुछ पहलुओं से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके अन्य पहलुओं से रोमांचित हूँ।

प्रधानमंत्री मोदी का पटना में विशाल रोड शो

रोड शो में भारी तादाद में युवा और महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर की तख्ती लिए हुए थे

- रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार भाजपा मुख्यालय में विधानसभा चुनाव रणनीति पर प्रदेश नेताओं के साथ वार्ता की।
- शुक्रवार को प्रधानमंत्री बिक्रमगंज में कई सड़क एवं बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे।

पटना, 29 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए सशस्त्र बलों के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की अपनी पहली यात्रा के दौरान आज पटना में मेगा रोड शो किया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को मोदी ने बिहार की अपनी पहली यात्रा के दौरान पटना हवाईअड्डे पर नवनिर्मित टर्मिनल का उद्घाटन किया और बिहटा हवाईअड्डे के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास भी किया। पटना हवाईअड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण 1200 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है, जिससे सालाना एक करोड़ यात्रियों को सुविधा मिलेगी जबकि बिहटा हवाईअड्डे के सिविल एन्क्लेव का निर्माण 1413 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिससे सालाना 50 लाख यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन और नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास करने के बाद पटना में रोड शो किया। उन्होंने पटना हवाईअड्डे से अपना रोड शो शुरू किया, जो वीरचंद पटेल रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्यालय पर समाप्त हुआ। सड़क किनारे प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया, जिनमें से अधिकांश लोगों के हाथ में तिरंगा था।

रोड शो के दौरान मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे जुटे थे, जिनमें ज्यादातर युवा थे। लोग ऑपरेशन सिंदूर लिखी तख्तियां लिए हुए थे।

मोदी ने इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उनके साथ बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

प्रधानमंत्री आज रात पटना के राजभवन में रुकेंगे और शुक्रवार को बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री करीब 50 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली कई सड़क और बिजली परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे।

जासूसी के संदेह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अत्यंत चिंताजनक है। यह देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस और उसके नेताओं में भी राष्ट्रभक्ति हो।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग उच्च पदों पर होते हुए भी देशहित से समझौता कर सकते हैं। मंत्री के पास कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं, और उनके पीए को भी वह सबकुछ मालूम होता है। अगर यह निजी सचिव पाकिस्तान के संपर्क में है, तो यह जासूसी की आशंका को जन्म देता है। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में तीन जज आज शपथ लेंगे

नयी दिल्ली, 29 मई। उच्चतम न्यायालय में तीन नये न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं जो शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

- ये हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. अंजारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.एस. चंदुरकर।

शीर्ष अदालत की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार इन तीनों न्यायाधीशों को न्यायालय परिसर के प्रशासनिक खंड स्थित ऑडिटोरियम में सुबह साढे दस बजे एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी जायगी।

इससे पहले केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज ही अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की जानकारी दी थी। तीनों न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण करने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़ कर 34 हो जाएगी। शीर्ष अदालत के लिए न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या इतनी ही है।

'आतंकवादियों को हमारे हवाले करो और पीओके खाली करो'

पाक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की वार्ता की पेशकश पर भारत की दो टूक

- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान के बारे में हमारा रुख स्पष्ट है, पहले वे हमें कुख्यात आतंकवादी सौंपें और पीओके को खाली करने की समय सीमा दें, उसके बाद ही कोई वार्ता होगी।

नयी दिल्ली, 29 मई। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ के भारत के साथ आतंकवाद सहित हर मुद्दे पर बातचीत की खुली पेशकश पर अपना रुख और साफ करते हुए आज कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत द्वारा सौंपी गयी सूची के आधार पर आतंकवादियों को हमारे हवाले करने तथा जम्मू कश्मीर से उसके अवैध कब्जे वाला हिस्सा खाली करने के बारे में ही बात की जाएगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां नियमित ब्रीफिंग में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा उनके विदेश दौरे के दौरान, भारत के साथ बातचीत की बार-बार की जा रही पेशकश के बारे में भारत की प्रतिक्रया पूछे जाने पर कहा, जहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, हमारा रुख स्पष्ट है। हमारे बीच कोई भी संबंध या संपर्क द्विपक्षीय होना चाहिए। हम दोहराना चाहेंगे कि आतंकवाद और बातचीत, एक साथ नहीं चल सकते। उन्हें भारत को उन कुख्यात आतंकवादियों को सौंपना होगा, जिनके रिकॉर्ड और सूची हमने कुछ साल पहले उन्हें सौंपी थी। जम्मू-कश्मीर पर बातचीत इस पर होगी कि जम्मू कश्मीर के उसके अवैध कब्जे वाला इलाका पाकिस्तान खाली करके हमें कब सौंपेगा।

जायसवाल ने कहा, जहाँ तक सिंधु जल संधि का सवाल है, यह तब तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय ढंग से और पूरी तरह से बंद नहीं कर देता। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।

पाकिस्तान में ऑपरेशन सिन्दूर के बाद लश्करे तैयबा के आतंकवादियों द्वारा जगह-जगह जलसे करने और उनमें पाकिस्तान सरकार के नेताओं एवं सेना के अफसरों की मौजूदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादियों का महिमामंडन करना, माला पहना कर उनका स्वागत-सत्कार करना और उन्हें बड़े मंच प्रदान करना हमारे लिये कतई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे यह फिर से पुष्टि होती है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को सरकार एवं सेना का समर्थन प्राप्त है।

खनन पट्टों में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अध्यक्ष की ओर से दायर एसएलपी पर राज्य सरकार को बजरी खनन पट्टा जारी करने के लिए दिशा- निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के बाद ही नए खनन पट्टे जारी करने को कहा था। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सीईसी की एक सिफारिश को छोड़कर, अन्य सिफारिशों को तत्काल लागू करने को कहा था। इन सिफारिशों के तहत सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और बकाया व लागू करों का भुगतान करने के बाद ही बजरी खनन की अनुमति दी जा सकती है। इसके बावजूद, नए खनन पट्टे देने के दौरान इन निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना देखने के लिए कमेटी गठित करने और इसकी सिफारिश पर खनन पट्टे देने के आदेश दिए हैं।

आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया

नयी दिल्ली, 29 मई। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगी और इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरूवार को जारी 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, जो इसकी मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी बातों, मजबूत वित्तीय क्षेत्र और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित है। हालांकि, इसने कहा कि संरक्षणवादी उपायों के बाद वैश्विक व्यापार के बारे में अनिश्चितता, लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता विकास के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए सकारात्मक जोखिम पैदा करती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी खपत में वृद्धि, बैंकों और कॉरपोरेट की स्वस्थ बैलेंस शीट, वित्तीय स्थितियों में सुधार और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर दिए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है। 2025-26 के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 6.5 प्रतिशत और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

'बार-बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सशस्त्र सेनाओं के भविष्य के लिये तैयार रहने की जरुरत पर जोर देते हुये, सिंह ने कहा कि उद्योग को उत्पादन बढ़ाने में एक दशक का समय लग सकता है, लेकिन सेनाएं वर्तमान जरुरतों को पूरा किये बिना पूरी दक्षता के साथ काम नहीं कर सकतीं। सिंह ने कहा, "(यह ठीक है कि) दस साल में हमें उद्योग से काफी आउटपुट मिलने लगेगा, लेकिन जो हमें आज चाहिये, वह तो आज ही चाहिये। हमें शीघ्रता से और मिलकर काम करने की जरुरत है। युद्ध सेनाओं को सशक्त बनाने से जीते जाते हैं।" "आपरेशन सिंदूर" के तहत, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करने के कई सप्ताह बाद, केन्द्र ने स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन स्टैल्थ फाइटर जैट, जो एडवान्स्ड मीडियम कॉम्बेट एयर-क्राफ्ट (एएमसीए) है, को बनाने की रुपरेखा को बुधवार को मंजूरी दे दी।

महाभियोग...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे में सवाल है कि क्या जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलेगा? वरिष्ठ वकीलों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, उपराष्ट्रपति ने कानूनी पुनर्विचार का आ ान किया है और सभी की निगाहें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पर टिकी हैं। न्यायमूर्ति वर्मा ने अक्टूबर 2021 और अप्रैल 2025 के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में भी सेवा दी।

राज्यसभा की आठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकता, क्योंकि उसके पास चार वोट कम हैं।

असम में न तो भाजपा और न ही कांग्रेस को दूसरे दलों से समर्थन मिलने का भरोसा है, इससे तीसरी पार्टी का दखल बढ़ने या अंतिम समय के कोई गठबंधन बनने की संभावना को बल मिलता है। कड़े मुकाबले को देखते हुए असम में काफी राजनैतिक उठापटक देखी जा सकती है।

राज्यसभा चुनाव के नतीजों से राज्यसभा के गणित में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा, लेकिन ये नतीजे तमिलनाडु व असम में भाजपा की पकड़ की कड़ी परीक्षा होंगे। ये इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के समीकरणों की झलक दे सकते हैं।

'पाकिस्तान की सेना सुनियोजित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नियुक्तियों जैसे मुद्दों पर जनरलों से मतभेद के बाद, खान अब दावा करते हैं कि "सैन्य प्रतिष्ठान ने उनकी बर्खास्तगी की साजिश रची" और 2024 के चुनावों को "इंजीनियर" किया, ताकि उन्हें और उनकी पार्टी को हाशिये पर डाला जा सके।

उनका संदेश स्पष्ट है, "जब तक सेना अपने संवैधानिक दायरे में नहीं लौटती, पाकिस्तान में असली लोकतंत्र संभव नहीं है।" खान की आलोचना पाकिस्तान के दीर्घकालिक नागरिक-सेना असंतुलन पर गहरा प्रहार है, जहाँ जनरल्स ने तीन दशकों से अधिक समय तक सीधे शासन किया है और निर्वाचित सरकारों के दौरान भी विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर वीटो पावर बनाए रखी है। उन्होंने वर्तमान सैन्य नेतृत्व, जो कथित तौर पर सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के अधीन है, पर अदालतों को प्रभावित करने, पत्रकारों को धमकाने और

- इमरान की वास्तविक सोच क्या है?

राजनीतिक विरोधियों को या तो चुप कराने या दल-बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। खान ने कहा, "वे राजनीतिक दलों को तोड़ रहे हैं और जनादेश को बंदूक की नोक पर कुचल रहे हैं।"

पाकिस्तान में सेना की खुली आलोचना दुर्लभ और खतरनाक मानी जाती है। अतीत में जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर नवाज़ शरीफ तक कई नेताओं को सेना के वर्चस्व को चुनौती देने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। खान का इस रास्ते पर चलना या तो एक रणनीतिक दांव है, जिससे वे जनता की सहानुभूति फिर से जीतना चाहते हैं, या फिर यह उनके बढ़ते राजनीतिक अलगाव के बीच हताशा का संकेत है।

आलोचकों का कहना है कि खान आज सेना को उन असफलताओं को दोषी ठहरा रहे हैं, जिनसे वे पहले लाभान्वित होते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। लाहौर के एक राजनैतिक विश्लेषक ने कहा, "जब सेना का हस्तक्षेप उनके पक्ष में था, तब इमरान खान ने उसे और मजबूती दी। अब वे नियम बदलना चाहते हैं।"

खान की इस कटु आलोचना की नई दिल्ली भी अनदेखी नहीं करेगी। भारतीय विश्लेषक लंबे समय से पाकिस्तान की सेना को भारत-पाक संबंधों में शांति और सामान्यीकरण में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। खान की टिप्पणियाँ इस धारणा को मजबूत कर सकती हैं कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें केवल दिखावा हैं।

खान का यह विद्रोह उन्हें फिर से राजनीतिक मुख्यधारा में ला पाएगा या उनके और ज्यादा दमन का कारण बनेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी पाकिस्तान के कुछ वर्गों, खासकर शहरी और युवा, में महत्व रखती है, जो उन्हें अभिजात्य वर्ग के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक मानते हैं।

हाई कोर्ट ने कनिष्ठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुमावत व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। खंडपीठ के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल पाई है, जिन्होंने भर्ती नियमों में संशोधन के जरिए सीआईटीएस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को चुनौती दी थी।

याचिकाओं में कहा गया था कि वे प्रदेश के विभिन्न आईटीआई कॉलेजों में 10 से 15 साल से गेस्ट फैकल्टी पर काम कर रहे हैं। इस दौरान, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने एक सितंबर 2023 को राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम,1975 में संशोधन कर दिया।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने 11 मार्च 2024 को भर्ती विज्ञापन निकाला और इसमें सीआईटीएस सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया। राज्य सरकार के भर्ती विज्ञापन और संशोधन आदेश को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने भी सीआईटीएस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की है, लेकिन सेवा में लेने के तीन साल के भीतर यह प्रमाण पत्र देने की छूट का भी प्रावधान है। राज्य सरकार ने सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है। इसलिए उन्हें सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने बताया कि केन्द्र सरकार की छूट उन मामलों के लिए है, जहां पर्याप्त संस्थाएं और अभ्यर्थी नहीं हैं, जबकि प्रदेश में यह सर्टिफिकेट कराने के लिए पर्याप्त संस्थाएं और उचित संख्या में अभ्यर्थी हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

चीन, अमेरिका को चीते की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

युद्धविराम की अपील कर रहे थे, जबकि उसी दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए।

पुतिन ने मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के शहरों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर सबसे भीषण हमले किए। ट्रम्प को आखिरकार यह स्वीकार करना पडा कि जब वे युद्धविराम की बात कर रहे थे, उस समय रूस की आक्रामकता बढ़ रही थी।

रूसी राष्ट्रपति ने ट्रम्प को तथा यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के उनके किसी भी प्रयास को पूरी तरह नजरअंदाज़ किया। वो भी तब, जबकि ट्रम्प पुतिन की भाषा में ही समाधान के सुझाव दे रहे थे, लेकिन पुतिन ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। बावजूद इसके, ट्रम्प यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ैलैंस्की के बारे में अपमानजनक भाषा का उपयोग करते रहे। पुतिन नई-नई शर्तें थोपते रहे।

रूस की अवज्ञा और धोखेबाज़ी से परेशान होकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव रखा, जिनमें उन देशों को दंडित करना शामिल था, जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे थे।

इससे मुख्य रूप से भारत और चीन प्रभावित होते, जो रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, और यही तेल रूस सरकार के खर्चों का, जिसमें युद्ध भी शामिल है, प्रमुख स्रोत है। यदि तेल बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाते तो रूसी राज्य की कमर टूट सकती थी।

अन्य प्रतिबंधों में रूस को अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के उपयोग से और अधिक वंचित करने की योजना भी थी।

अमेरिका ने अब तक विदेशों में जब्त किए गए रूसी फंड का उपयोग यूक्रेन को सहायता देने या युद्ध के लिए करने की बात भी नहीं कही थी। साथ ही यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी हथियारों का उपयोग रुस के अंदर गहरे हमलों के लिए भी किया जाना था।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वास्तव में इनमें से किसी भी उपाय की घोषणा करने से परहेज किया है। इसके विपरीत, ओवल ऑफिस से अपनी नवीनतम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि रुस पर नए प्रतिबंध उनके द्वारा शुरु की गई शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल सकते हैं।

यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपने घोषित लक्ष्यों और लक्ष्यों की कोई स्पष्ट उपलब्धि नहीं मिलने पर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के लिए बार-बार स्वयं को श्रेय दिया है। उन्होंने बार-बार दावा किया कि उन्होंने ट्रेड के मुद्दे का इस्तेमाल किया, जिसके कारण युद्धविराम हुआ।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा इस दावे का बार-बार खंडन किया गया है।

इस प्रकार अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल की क्या उपलब्धि है, झूठ का एक पुलिंदा और विफलताओं की एक लंबी श्रृंखला।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908